

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15022023-243622
SG-DL-E-15022023-243622असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]	दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2023/माघ 25, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 484
No. 5]	DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2023/MAGHA 25, 1944	[N. C. T. D. No. 484

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

सं.13/नियम/ डी.एच.सी.—दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 एवं 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, एतद् द्वारा उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, भाग V के अध्याय 3 के भाग ख के नियम 1 के खंड (xxi) के स्पष्टीकरण में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

1. निम्नलिखित को उच्च न्यायालय नियम और आदेश, भाग V के अध्याय 3 के भाग ख के नियम 1 के खंड (xxi) के वर्तमान स्पष्टीकरण हेतु प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"स्पष्टीकरण- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, निवारक निरोध, दया याचिका और मृत्यु दंडादेश के लघुकरण से संबंधित मामलों की प्रारंभिक और अंतिम सुनवाई दो न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष होगी।"

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

रविंदर डुडेजा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI
NOTIFICATION

Delhi, the 14 February, 2023

No.13/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Sections 122 and 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendment in the explanation to Clause (xxi) of Rule 1 of Part B of Chapter 3 of the High Court Rules & Orders, Volume V:-

1. The following shall be substituted for the existing Explanation to Clause (xxi) of Rule 1 of Part B of Chapter 3 of the High Court Rules & Orders, Volume V:-

“Explanation—The preliminary and final hearing of cases under Article 226 of the Constitution of India, relating to habeas corpus, preventive detention, mercy petition and commutation of sentence of death, shall be before a Bench of two Judges.”

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

RAVINDER DUDEJA, Registrar General.